डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 1 अप्रैल, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 अप्रैल, 2025

| वर्ष 68 | अंक 21 | भोपाल | 1 अप्रैल, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारिता आंदोलन को आगामी 4 वर्ष में नए मुकाम पर पहुंचाएंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

दूध पर बोनस देने के साथ ही अन्य क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को करेंगे लाभान्वित ● अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 अन्तर्गत हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार सर्वजनकल्याण के संकल्पों के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक पारदर्शितापूर्ण कार्य शैली के कारण अन्य क्षेत्रों के साथ सहकारी क्षेत्र में समृद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता का लाभ पहुंचाने के लिये बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय के भाव के अनुसार कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिया है। मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में निश्चित ही नए दौर की नई कहानी लिखेगा। गुजरात में दूध पर बोनस की जिस तरह व्यवस्था है, मध्यप्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन के लिए काफी बड़ा क्षेत्र है और हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी उद्योग क्षेत्र के साथ सहकारिता ने कार्य करने की पहल की है। मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति दी जा रही है। अब सहकारिता क्षेत्र में व्यवस्थाएं काफी पारदर्शी हैं और मध्यप्रदेश में सहकारिता के विभिन्न आयामों पर कार्य किया जाएगा। आने वाले चार वर्ष में सहकारिता आंदोलन को नए मुकाम पर पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में पधारे प्रदेश भर के प्रतिभागियों का स्वागत किया।

उन्होंने सहकारिता विभाग में नवनियुक्त सहकारी निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता विभाग के प्रयासों की सराहना की।

भारत में प्रचलित व्यवस्थाओं से सीखते हैं अन्य देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत में सहकारिता का इतिहास पुराना है। भारत में वर्षों पूर्व अश्वमेघ यज्ञ की परंपरा रही थी। लेकिन भारत ने किसी राष्ट्र पर कब्जा नहीं किया। छोटे-छोटे राज्यों की स्वायत्तता को खत्म नहीं होने दिया बल्कि उन्हें साथ लेकर कार्य किया और उनके स्वावलंबन को भी जीवंत रखा। सच्चे अर्थों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भावना का पालन करने वाला कोई राष्ट्र है तो वह भारत है। जब यह कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया: ....तो इसका अर्थ है सभी को परस्पर जोड़ना और अपने लाभ में उन्हें सहभागी बनाना। यह वसुधैव कुटुम्बकम जैसे वेद वाक्य का लघु रूप है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्व में भारत की गरिमा बढ़ाने का कार्य किया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी की भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश में होगा कार्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सहकारिता के मूल भाव के अनुरूप बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की कल्पना की। इसे साकार करने के लिए सहकारिता का दायित्व केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह को दिया गया। केंद्र सरकार ने सहकारिता में सभी के कल्याण का ध्यान रखा है। मध्यप्रदेश में भी इसी तर्ज पर कार्य हो रहा है। सहकारिता अधिनियम में परिवर्तन के फलस्वरूप सोसायटी के रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 दिन में संभव होगा। पूर्व में यह अवधि 90 दिवस थी। पूर्व की व्यवस्था में अनेक कठिनाईयों को सामना करना होता था। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पहल हुई। सहकारिता को उन्होंने बहुउद्देश्यीय और बहुआयामी बनाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा औद्योगीकरण में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, सहकारिता की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मध्यप्रदेश किसानों, गौ पालकों और मत्स्य पालकों को सहकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ दिलवाकर इस क्षेत्र में शिखर पर पहुंचेगा।

सहकारी ध्वजारोहण कर कैलेण्डर, मैन्युअल और परिपत्र पुस्तिका का किया विमोचन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुरूआत में सहकारी ध्वजारोहण कर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर, पैक्स कार्य मैन्युअल और सहकारिता में सहकार, पैक्स पुनर्गठन और व्यवसाय संवर्धन के महत्वपूर्ण परिपत्रों की पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माइक्रो एटीएम पखवाड़े का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पैक्स, दुग्ध सहकारी संस्थाओं और मत्स्य पालक सहकारी संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए। इन संस्थाओं में विदिशा, इंदौर और खरगोन की संस्थाएं शामिल हैं।

कार्यक्रम को सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता से समृद्धि का मंत्र दिया है। मध्यप्रदेश सहकारिता क्षेत्र में अग्रणी हो रहा है। हाल ही में जीआईएस-भोपाल में नया अध्याय जोड़ा गया जब सीपीपीपी अर्थात को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विषय सामने आया। सहकारिता विभाग में कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि होगी स्थापित : श्री सारंग

सहकारिता विभाग के सभी 25 अनुकंपा नियुक्ति आदेशों का वितरण ● ई-पैक्स प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला

भोपाल :सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारिता का संकल्प नए आयाम स्थापित करेगा। सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि स्थापित होगी। जरूरत है मेहनत, लगन और पारदर्शिता की। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नवाचार से किये गये कार्य के जरिये व्यक्ति नई ऊंचाईयों को पा सकता है। मंत्री श्री सारंग बुधवार को अपेक्स बैंक परिसर स्थित समन्वय भवन में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजनांतर्गत ई-पैक्स प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता विभाग में 25 अनुकम्पा नियुक्ति पाने वालों को नियुक्ति आदेश भी प्रदान किये। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णबाल भी उपस्थित थे।

ब्रांडिंग और दृढ़ता के साथ काम करने की भावना स्थापित करें

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता में ब्रांडिंग और दृढ़ता के साथ काम करने की भावना स्थापित हो। नित नये नवाचार के जरिये अपनी पहचान बनाएं। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में उदाहरण है जिन्होंने काम किया लोग उन्हें ही याद रखते है। इसलिये स्वयं अपने व्यक्तित्व निर्माण के साथ उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिले और लोग उन्हें याद रखे।

पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में मध्यप्रदेश प्रथम

मंत्री श्री सारंग ने कहा की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की चाहत सफल बनाती है। सहकारिता के माध्यम से ही अर्थ-व्यवस्था का उन्नयन किया जा सकता है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। कम्प्यूटराइजेशन की इस बड़ी मुहिम में पारदर्शिता के साथ हमारा प्रयास सफल रहा।

सीपीपीपी मॉडल की सराहना

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि मध्यप्रदेश का नया सीपीपीपी (को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पारटरशिप) मॉडल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सराहना हुई। यही नहीं राज्य सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में 2500 करोड़ के एम.ओ.यू. भी किये। मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वालों को भी जिम्मेदारी के साथ दिये गये काम को सम्पादित करने को कहा। उन्होंने युवाओं से आहवान किया कि पारदर्शिता, निपुणता और व्यावसायिकता के साथ काम करें। इस मौके पर उन्होंने एक मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया।

अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। आयुक्त सह पंजीयक श्री मनोज पुष्प, श्री पी.एस. तिवारी और श्री बी.एस. शुक्ला उपस्थित रहे।

अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों को नियुक्ति पत्र

मंत्री श्री सारंग ने इंदौर की कु. प्रेरणा सोनी, टीकमगढ़ की श्रीमती तरूणा झाम और श्रीमती ऊषा सेन, नरसिंहपुर की कु. पूर्णिमा गहलोद, शाजापुर की कुमारी सौम्या मालवीय, महाराष्ट्र वर्धा की कु. योगिता सतपाल, सतना की श्रीमती शुभांगी श्रीवास्तव और श्रीमती सुभद्रा सिंह, जबलपुर की कु. कंचन दाहिया और श्रीमती भावना तिवारी, रतलाम की सुश्री नेहा सोलंकी, सागर के ओजस्वा यादव और श्री अमित जाटव, बालाघाट के श्री विजय राज सोनवे, रीवा के श्री संजय रत्नाकर, सीहोर श्री मुकेश कुमार और श्री दीपेश सिसोदिया, विदिशा के विनोद रायकवार, बैतूल के श्री हेमंत प्रधान, मुरैना के श्री अक्षय चौहान, रीवा के श्री देशराज वर्मा, भोपाल के श्री शुभम पांचाल, श्योपुर के श्री जयकुमार रेगर, सिवनी के श्री आशीष कोरी और सीधी के श्री राजेश कुमार पटले को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

पैक्स कंप्यूटराइजेशन के सफल क्रियान्वयन के लिए पैक्स प्रबंधकों को मिलेगी 5000 रु. की प्रोत्साहन राशि

भोपाल : मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग में अग्रणी रहा है। केंद्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में मध्यप्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के डिजिटाइजेशन एवं सॉफ्टवेयर आधारित अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए गठित स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एसएलआईएमसी) की बैठक मंत्रालय में हुई। समिति ने सर्व सम्मति से पैक्स प्रबंधकों/ सहायक समिति प्रबंधकों को एकबारगी राशि 5000 रूपये की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए 15 मई 2025 तक पैक्स को ई-पैक्स (तातारीख सॉफ्टवेयर पर कार्यशील होना) घोषित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) के 2 मास्टर ट्रैनर्स, जिनके बैंक की न्यूनतम 50 प्रतिशत पैक्स को उक्त दिनांक तक ई-पैक्स घोषित किया गया है, को प्रतिमाह राशि 1000 रुपए का प्रोत्साहन आगामी 12 माह तक प्रदान किया जाएगा।

पैक्स प्रबंधकों को दी जाने वाले राशि का वहन अपैक्स बैंक तथा मास्टर ट्रेनर को दी जाने वाली राशि का वहन संबंधित डीसीसीबी द्वारा किया जाएगा। इस तरह अच्छे कार्य को सराहना देने में भी मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है।

बैठक में श्रीमती सी सरस्वती(मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल), श्री मनोज कुमार गुप्ता (प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक), श्री अम्बरीश वैद्य (संयुक्त आयुक्त, आयुक्त सहकारिता प्रतिनिधि), श्रीमती अंजुली धुर्वे (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डीसीसीबी रायसेन), श्री विनय प्रकाश सिंह (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डीसीसीबी विदिशा) एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता आंदोलन को आगामी 4 वर्ष में .....

अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव मत्स्य पालन श्री डी.पी. आहूजा, राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय की मुख्य महा प्रबंधक श्रीमती सी. सरस्वती एवं बड़ी संख्या में प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, जिला सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, पैक्स, दुग्ध एवं मत्स्य समितियों के साथ ही सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार गुप्ता ने आभार माना।

महिला स्वास्थ्य एवं कानूनी अधिकार विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा सहकारिता विभाग की महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए "महिला स्वास्थ्य एवं उनके कानूनी अधिकार" विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, पोषण, कानूनी अधिकार एवं संरक्षण संबंधी विषयों पर जागरूक करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिभागियों के पंजीयन एवं प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच से हुआ। बड़ी संख्या में महिला अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्यशाला में शामिल हुईं। प्रारंभ में सभी प्रतिभागियों का पंजीयन किया गया, इसके साथ ही महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान रक्त जांच, ब्लड प्रेशर जांच एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महिलाओं को नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाने एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

महिला स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष सत्र

कार्यशाला के अंतर्गत विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी।

1. **खाद्य अभिपुष्टिकरण एवं प्रदूषण से बचाव:**
   इस सत्र में श्रीमती प्रियंका बघेल, क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल ने महिलाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्यवर्धक खानपान एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपने आहार में पोषक तत्वों को संतुलित रूप से शामिल करना चाहिए एवं खाद्य प्रदूषण से बचने के लिए जागरूक रहना चाहिए।
2. **महिला स्वास्थ्य पर चर्चा:**
   इस सत्र का नेतृत्व डॉ. निधि दीवान (चिकित्सक, भोपाल) ने किया। उन्होंने महिलाओं को उनके स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जागरूक किया। इस दौरान हार्मोनल बदलाव, मासिक धर्म, मातृत्व स्वास्थ्य एवं उम्र के अनुसार महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों पर विशेष चर्चा की गई।
3. **महिलाओं के कानूनी अधिकार:**
   इस महत्वपूर्ण सत्र में एडवोकेट श्री एस.आर. राज एवं एडवोकेट श्रीमती रजनी अहिरवार ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, संपत्ति अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न एवं अन्य कानूनी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने इस सत्र के दौरान अपने व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे और कानूनी विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त किए।
4. **महिला स्वास्थ्य एवं उपचार:**
   इस सत्र का संचालन डॉ. अनीता गुप्ता (चिकित्सक, भोपाल) ने किया। उन्होंने महिलाओं को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु चिकित्सा परामर्श दिया। महिलाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, समय पर चिकित्सा जांच करवाने एवं उचित उपचार की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय श्रीमती रेखा पिप्पल ने किया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया एवं वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया। कार्यशाला के समापन सत्र में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए एवं इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों की निरंतरता पर बल दिया।कार्यक्रम के दौरान संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने प्रश्न पूछे और विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त किए। इस कार्यशाला से महिलाओं को न केवल अपने स्वास्थ्य एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त हुई, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी मिली।यह कार्यशाला ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सिद्ध हुई एवं इसमें भाग लेने वाली महिलाओं ने इसे अत्यंत लाभकारी बताया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी सहभागियों ने आयोजकों एवं विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

'सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है"

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिनांक 19 जून 2024 को प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2025 को द्वितीय अंर्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। जिसका थीम सहकारी समितियां एक बेहतर दुनियां का निर्माण करती है, रखा गया है। जो सहकारी समितियों के स्थाई वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। सहकारी समितियों कई वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके लिए आवश्यक समाधान प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 को प्रथम अंर्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। जिसके द्वारा गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सामाजिक एकीकरण में सहकारी समितियों के योगदान को उजागर किया गया था।

अंर्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारी सम्मेलन व आभसभा में किया गया। जिसमें दुनियां के 100 से अधिक देशो के सहकारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा भाग लिया गया। इस सम्मेलन को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुएँ कहाँ कि 'भारत के लिए सहकारिता जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होने भारत की सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होने वर्ष 2025 को अंर्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को धन्यवाद दिया। इस सम्मेलन में सहकारी पहचान की पुष्टि करना, सहायक नीतियों को सक्षम बनाना, मजबूत नेतृत्व विकसित करना तथा स्थायी भविष्य का निर्माण करना, इन चार बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

इस सम्मेलन में इफको के प्रबंध निर्देशक डॉ उदय शंकर अवस्थी को सहकारी आंदोलन में उनके अपार योगदान के लिए आईसीए द्वारा दिये जाने वाला सर्वोच्य सम्मान रोशडेल पायनियर्स 2025 प्रदान किया गया। सम्मेलन में शामिल युवाओं के लिए कोपाथॉन का आयोजन किया गया। जिसमें खेलो के माध्यम से युवाओं को सहकारी समाधान प्राप्त करना सिखाया गया। आईसीए वर्ष 2025 में युवाओं को सहकारी आंदोलन से जोडने के लिए कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।

यह वर्ष वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए एक सुअवसर है। जिसमें वे अपने प्रभाव व उपलब्धियों का वर्षभर जश्न मनाकर ऐसे भविष्य की योजना बना सकते है जो सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करें। जय सहकारिता।

शिरीष पुरोहित, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव

भिण्ड में दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

भिण्ड, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित भिण्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम का समापन सफलता पूर्वक हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम19 मार्च से 20 मार्च 2025 तक चला, जिसमें उपभोक्ता सहकारी भंडार की महिला कर्मचारियोंको कार्य में कुशलता, नेतृत्व विकास और सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रशिक्षित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन श्री रामकुमार शर्मा (प्रबंधक, जिला संघ भिण्ड)के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सहकारी संघ भिण्ड प्रमुख एवं प्रबंधक श्री रामकुमार शर्माने की। उन्होंने सहकारिता के महत्व और उपभोक्ता भंडार की महिला सहकारी समितियों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सहकारिता से समृद्धि संभव है और इसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकते हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शैलेन्द्र सिंह गुर्जर रहे, जिन्होंने सहकारी समितियों के उत्थान और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओंकी जानकारी दी। उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण के अवसरों पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया गया।

श्री निर्पत सिंह भदौरिया (पूर्व प्रबंधक) ने फल, फूल एवं सब्जियों की उन्नत खेती तकनीकों, नर्सरी प्रबंधन, टिशू कल्चर एवं ग्रीन हाउस खेती पर व्यावहारिक जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने भिण्ड जिले की सिंचाई व्यवस्था पर भी चर्चा की और फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोग नियंत्रण के आधुनिक उपायों पर विस्तृत जानकारी दी।

श्री हृदेश कुमार राय (जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक) ने सहकारी संस्थाओं में सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और सहकारिता में रोजगार के अवसरों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना, छत्तीसगढ़ राज्य की अंबिकापुर कचरा प्रबंधन समिति और सीएचसीडीएस से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला।

श्रीसुनील सिंह (मैनेजर, उपभोक्ता भंडार समिति) ने जलवायु परिवर्तन के बागवानी फसलों पर प्रभाव और उससे निपटने की रणनीतियों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर पड़ने वाले प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है और आधुनिक कृषि तकनीकों का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए।

श्रीआर. ए. शर्मा (पूर्व अंकेक्षण अधिकारी) ने सहकारी समितियों में अंकेक्षण, ऑडिट प्रक्रिया, लेखा-जोखा प्रबंधन एवं जैविक खाद निर्माणकी विधियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए उचित लेखा-जोखा बनाए रखना कितना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल एवं जिला सहकारी संघ भिण्ड का यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने, पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने एवं आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की विभिन्न उपभोक्ता भंडार सहकारी समितियों की 40 से अधिक महिला पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण शामिल हुए।

इसके अलावा अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि जैसेश्री निर्पत सिंह भदौरिया (पूर्व प्रबंधक जिला सहकारी संघ भिण्ड), सुनील सिंह (मैनेजर उपभोक्ता भंडार), श्री रामकुमार शर्मा (प्रबंधक जिला सहकारी संघ भिण्ड), श्री आर. ए. शर्मा (पूर्व सहकारी निरीक्षक), श्री हृदेश कुमार राय (जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव) सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर द्वारा दिनांक18 मार्च 2025 एवं 20 मार्च 2025को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गोदना एवं मंगलज, जिला शाजापुर में एक दिवसीयप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों मेंगोदना समिति के प्रबंधक श्री राम नारायण परमार, ऑपरेटर श्री संजय मेवाड़ा, विक्रेता श्री ज्ञान सिंह कुंभकार एवं मंगलज समिति की प्रबंधक सुश्री रचना सिसोदिया, ऑपरेटर श्री नरेंद्र परिहार, विक्रेता श्री दीपक पाटीदार सहित समस्त सम्माननीय सदस्य एवं कृषक बंधुउपस्थित रहे।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों, सहकारी समितियों की नवीन नीतियों एवं बहुउद्देश्यीय समितियों के लाभों से सभी को अवगत कराना था।जिला शिक्षा प्रशिक्षक श्री प्रदीप कुमार रैकवारने प्रशिक्षण के दौरान निम्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की—

- सहकारिता की पृष्ठभूमि एवं उसका महत्व
- सहकारी सिद्धांतों की व्याख्या एवं उनके अनुप्रयोग
- सहकारी समितियों की नवीन नीतियाँ एवं उनसे मिलने वाले लाभ
- समिति के बहुउद्देश्यीय स्वरूप से होने वाले फायदे
- सहकारिता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास

समिति प्रबंधकों द्वारा संस्था की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों एवं भविष्य की योजनाओं से सभी को परिचित कराया गया। अंत में सहकारिता की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आभार व्यक्त किया गया।

मछुआ सहकारी समिति मर्यादित रम्पा, सिंगरौली प्रशिक्षण शिविर संपन्न

जबलपुर: सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर द्वारा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, रम्पा, जिला सिंगरौली में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समिति के अध्यक्ष श्रीमती वंदना मौर्या सहित समिति के अन्य सदस्य, कर्मचारी तथा संभावित सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मछुआरों को सहकारी समिति के संचालन, मत्स्य पालन तकनीकों, सरकारी योजनाओं एवं आधुनिक व्यावसायिक तौर-तरीकों की जानकारी देना था। साथ ही, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया गया।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई:

1. सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली – समिति के सुचारू संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय।
2. मत्स्य पालन के आधुनिक तकनीक – बेहतर उत्पादन और मत्स्य पालन के नवीन तरीकों की जानकारी।
3. सरकारी योजनाओं की जानकारी – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वित्तीय सहायता योजनाएँ, अनुदान एवं ऋण सुविधाएँ।
4. कौशल उन्नयन और व्यावसायिकता – मछुआरों को अपने व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाने के उपाय।
5. पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास – जल स्रोतों का संरक्षण और मत्स्य पालन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की रणनीतियाँ।

इस प्रशिक्षण शिविर में मछुआरों को मत्स्य पालन के नवीनतम तकनीकों और वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों पर मार्गदर्शन दिया।

समिति की अध्यक्ष श्रीमती वंदना मौर्याने कहा,"यह प्रशिक्षण हमारे मछुआ भाइयों एवं बहनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इससे वे अपनी आजीविका को अधिक संगठित, लाभदायक और तकनीकी रूप से उन्नत बना सकेंगे। सहकारी समितियाँ जब मजबूत होंगी, तब हमारे समुदाय का भी विकास होगा।"शिविर में भाग लेने वाले मछुआरों और समिति के सदस्यों ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा किइस प्रकार के प्रशिक्षण से उन्हें नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, जिससे उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

"सहकारिता से युवा विकास" विषय पर निबंध प्रतियोगिता संपन्न

इंदौर / नौगांव। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025के अवसर पर युवाओं को सहकारिता से जोड़ने और उनमें इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य सेमध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर एवं नौगांवमें कॉलेजमें"सहकारिता से युवा विकास" विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इंदौर में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर के तत्वावधान में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. चंदा तलेरा जैन, व्याख्याता डॉ. शीतल ब्रह्मणे, डॉ. आरती चौहान, डॉ. पल्लवी गुप्ता, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट, प्रशिक्षक श्री राहुल श्रीवास एवं श्री सुयश शर्मा उपस्थित रहे।

नौगांव में निबंध प्रतियोगिता संपन्न

पीएमश्री शासकीय बापू डिग्री कॉलेज, नौगांव में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत 21 मार्च 2025को निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 50 से अधिक छात्रोंने भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। विजेताओं को 26 मार्च 2025को आयोजित विशेष समारोह में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पी. के. मिश्राके कर कमलों द्वारा प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

सहकारिता से युवा विकास: एक सशक्त भविष्य की ओर

सहकारिता, सामाजिक और आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो"सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय"के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक प्रयासों से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और लोगों को समान अवसर प्रदान करना है।

युवाओं के लिए सहकारिता के लाभ:

- **रोजगार के अवसर:** सहकारी समितियां युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान करती हैं।
- **सामूहिक नेतृत्व और भागीदारी:** सहकारिता युवाओं को नेतृत्व, टीम वर्क और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है।
- **आर्थिक स्थिरता:** सहकारी संगठनों से जुड़कर युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने उद्यम को सफल बना सकते हैं।
- **सामाजिक समरसता:** सहकारी मॉडल समाज में एकता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है।
- **सतत विकास:** सहकारिता पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

विजेताओं का सम्मान

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को26 मार्च 2025को आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. पी. के. मिश्रा एवं अन्य अतिथियों ने युवाओं को सहकारी आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सहकारिता से युवा सशक्त बन सकते हैं तथा समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस आयोजन के माध्यम से छात्रों में सहकारिता के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे वे इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को समझें और सक्रिय भागीदारी निभाएं। सहकारिता से युवा न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं।

माही नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPO's के कार्यक्रम का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ

नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहानने आज "Strengthening FPOs – Empowering Farmers" कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम माही नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPO's द्वारा ए.पी. शिंदे सभागृह, पूसा, नई दिल्लीमें आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान ने किसानों के हित में सरकार की6 सूत्रीय रणनीति पर प्रकाश डाला और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा की।

कृषि की मजबूती के लिए 6 सूत्रीय रणनीति

श्री चौहान ने कहा कि भारत में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके लिए खेती से आजीविका चलाना कठिन होता है। इसलिए सरकार ने खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए 6 प्रमुख बिंदुओं पर काम करने की रणनीति बनाई है:

1. प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना
2. उत्पादन लागत घटाना
3. उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना
4. आपदा की स्थिति में नुकसान की भरपाई
5. कृषि का विविधीकरण
6. धरती की सेहत का ख्याल रखना

FPO: छोटे किसानों के लिए लाभकारी योजना

श्री चौहान ने बताया कि एफपीओ (Farmer Producer Organizations) का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन लागत को कम करना और किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाना है। उन्होंने कहा, "संघे शक्ति कलियुगे" यानी संगठित होकर ही किसान अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अब तक देशभर में 10,000 नए एफपीओ बनाए गए हैं, जो किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं।

सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

- टेक्नोलॉजी को लैब से खेत तक पहुंचाने पर जोर
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा रु. 3 लाख से बढ़ाकर रु. 5 लाख
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता
- डीएपी और यूरिया पर सब्सिडी जारी रहेगी
- प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर 0%
- सोयाबीन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 27.5% तक बढ़ाई
- बासमती चावल के निर्यात पर शून्य शुल्क

किसानों को मिलेगा उचित दाम

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है। टमाटर, आलू और प्याज के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। अगर किसी उत्पाद के दाम पिछले साल की तुलना में10% तक गिरते हैं, तो सरकार किसान को सीधा वित्तीय सहयोग देगी। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना, भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मोहिनी मिश्र, और सैकड़ों एफपीओ के सदस्य किसान भाई-बहन एवं कृषि वैज्ञानिक उपस्थित रहे। श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों और खेती को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

भोपाल, 1 अप्रैल, 2025

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025: महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गठन पर कार्यशाला आयोजित

जबलपुर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सहकारिता आंदोलन से जोड़ने के उद्देश्य से महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गठन प्रक्रिया पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर के सभागार में संपन्न हुई। कार्यशाला में महिलाओं को सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली, उनके लाभ तथा पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर एक मजबूत सहकारी समिति का गठन करना था, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाए और उनके समाज एवं परिवार में प्रभावी भूमिका को मजबूत करे। महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्योग, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग आदि के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यशाला के प्रमुख बिंदु

1. सहकारी समितियों की अवधारणा एवं कार्यप्रणाली
   - o सहकारी समितियों का महत्व और उनकी कानूनी प्रक्रिया।
   - o महिलाओं के लिए सहकारी समितियों के लाभ और अवसर।
2. गठन प्रक्रिया एवं पंजीकरण
   - o महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गठन के लिए आवश्यक दस्तावेज।
   - o पंजीकरण की प्रक्रिया, कानूनी औपचारिकताएँ और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता।
3. वित्तीय एवं आर्थिक सहयोग
   - o सहकारी समितियों के लिए सरकारी अनुदान, ऋण योजनाएँ एवं बैंकिंग सुविधाएँ।
   - o स्व-सहायता समूह (SHG) एवं महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन।
4. व्यावसायिक एवं प्रबंधन कौशल विकास
   - o महिला सदस्यों को व्यापारिक अवसरों और विपणन रणनीतियों की जानकारी।
   - o सफल महिला सहकारी समितियों के उदाहरण प्रस्तुत कर प्रेरित किया गया।

कार्यशाला मेंमुख्य अतिथि श्री वी. के. बारवे (प्रधानाचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर) एवं विशिष्ट अतिथिश्री यशवर्धन पाठक (प्रख्यात सहकारिता विशेषज्ञ) उपस्थित रहे। उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार, सहकारिता एवं आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व पर प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए।

श्री वी. के. बर्वे के विचार

"सहकारिता केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ता है। महिलाओं की भागीदारी से सहकारी समितियाँ और अधिक सशक्त बन सकती हैं। सरकार महिलाओं को सहकारी संगठनों में शामिल होने के लिए कई योजनाएँ एवं आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। हमें इसे अपनाना चाहिए और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएँ यदि संगठित होकर कार्य करें, तो वे न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती हैं, बल्कि समाज में भी एक सशक्त बदलाव ला सकती हैं।

श्री यशवर्धन पाठक के विचार

"सहकारी समितियाँ महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं, जहाँ वे न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं, बल्कि नेतृत्व क्षमता भी विकसित कर सकती हैं। हमें पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करना होगा।"

उन्होंने यह भी जोर दिया कि महिलाओं को सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, दुग्ध उत्पादन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी लेनी चाहिए, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। दोनों वक्ताओं ने महिलाओं से अपील की कि वे सहकारी समिति के गठन में सक्रिय भूमिका निभाएँ, इसका नेतृत्व करें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार और सहकारिता विभाग हर संभव सहायता प्रदान करेगा ताकि यह समिति सफलतापूर्वक कार्य कर सके।

इन विचारों से प्रेरित होकर, उपस्थित महिलाओं ने सहकारिता के माध्यम से एक सशक्त संगठन बनाने का संकल्प लियाऔर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गठन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मध्यप्रदेश ने कृषि में किए कई नवाचार, इसलिए देश में है अव्वल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की उर्वर धरा में खेती-किसानी लाभ का व्यवसाय है। हमने इसी दिशा में काम किया। नई कृषि विधियों को अपनाया, कई नवाचार किए। यही कारण है कि आज मध्यप्रदेश कृषि विकास के मामले में पंजाब, हरियाणा और अन्य कई राज्यों से आगे निकलकर देश में अव्वल स्थान पर है। हम खेती-किसानी और किसान दोनों की समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में नेशनल डिफेंस कॉलेज की ओर से मध्यप्रदेश आए अध्ययन यात्रा दल को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि एवं सहकारिता में मध्यप्रदेश में बीते दशकों में लगातार काम हुआ है। खेती के साथ-साथ सिंचाई पर भी हमने काम किया है। वित्त वर्ष 2002-03 तक मध्यप्रदेश में मात्र 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी। आज मध्यप्रदेश की 55 लाख से अधिक कृषि हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित क्षेत्र में लेकर आए हैं। हम किसानों को सुविधा सम्पन्न बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगले तीन सालों में हमारी सरकार प्रदेश के 30 लाख किसानों को न केवल सोलर पम्प देगी, वरन् उनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सोलर ऊर्जा का क्रय भी करेगी। इससे किसानों को दोहरा फायदा होगा। इसके अलावा हम किसानों को मात्र 5 रूपए की राशि पर बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऊर्जा के मामले में भी आगे है। देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला प्रदेश मध्यप्रदेश है। दिल्ली मेट्रो भी मध्यप्रदेश की बिजली से चलायमान है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी), नई दिल्ली द्वारा "राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीति" विषय पर आयोजित अध्ययन यात्रा के लिए मध्यप्रदेश राज्य की यात्रा के लिए आए दल ने सौजन्य भेंट की। देश के 5 मित्र देशों के प्रतिनिधि भी अध्ययन दल के साथ मध्यप्रदेश आए हैं। एनडीसी द्वारा पूरे देश के लिए ऐसे 8 अध्ययन समूह तय किए गए हैं, जिनमें से 16 सदस्यीय एक समूह मध्यप्रदेश की अध्ययन यात्रा पर है। मध्यप्रदेश आए यात्रा दल को यहां प्रदेश में 'कृषि एवं सहकारिता' अध्ययन शीर्षक दिया गया है। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी को इस समूह को मध्यप्रदेश की अध्ययन यात्रा कराने का दायित्व मिला है।

अध्ययन यात्रा दल ने बीते दिनों मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों का फील्ड विजिट कर कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति का अध्ययन किया और देखा कि मध्यप्रदेश ने इन दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन प्रगति हासिल की है। अध्ययन दल ने पाया कि सरकार की नीतियों से किसानों की समृद्धि बढ़ी है। वहीं स्व-सहायता समूहों के जरिए प्रदेश में आजीविका विकास विशेषकर महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश आए अध्ययन दल से परिचय प्राप्त किया और दल से आग्रह किया कि उज्जैन जरूर जाइए, महाकाल के दर्शन कीजिये और देखिये कि धार्मिक पर्यटन के मामले में म.प्र. कितने आगे बढ़ा हैं। सदियों पुराने श्री महाकाल मंदिर का विकास कर हमारी सरकार ने श्री महाकाल महालोक तैयार किया। इसमें भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति, उनका पार्वती से विवाह, सती कथा का प्रसंग सहित उनके जीवन के सभी प्रमुख पक्षों (तांडव मंत्र में दी गई 108 मुद्राओं सहित) को जीवंत कर प्रतिमाओं के रूप में उकेरा है। श्री महाकाल महालोक हमारी आस्था है, हमारी पूंजी भी है।

प्रदेश में हर खेत तक पानी पहुंचाने का भागीरथी कार्य: डॉ. यादव

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में तेज गति से हो रहा विकास

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में "नदी जोड़ो अभियान" के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने का भागीरथी कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के लिए यह गर्व की बात है किकेन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबलजैसी दो बहुउद्देशीय नदी जोड़ो परियोजनाओं का श्रीगणेश हुआ है।

नर्मदा-क्षिप्रा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने रु.2,489.65 करोड़ की नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाका लोकार्पण किया। इस परियोजना से100 ग्रामों की 30,218 हेक्टेयर भूमिमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना के माध्यम से ओंकारेश्वर जलाशय से जल उद्वहन कर पाईपलाइन द्वारा जल पहुंचाया जाएगा।

प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य

- किसानों को आर्थिक सहयोग:प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को प्रतिवर्ष रु. 12,000 की सहायता।
- गेहूं उपार्जन:सरकार ने रु. 2,600 प्रति क्विंटलकी दर से गेहूं खरीदने का निर्णय लिया।
- पशुपालन को बढ़ावा: 10 गाय पालने वालों को अनुदान औरदुग्ध उत्पादकों को रु.5 प्रति लीटरकी प्रोत्साहन राशि।

महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ

- लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा।
- स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षणऔर सरकारी नौकरियों में35% आरक्षणलागू।
- रेडीमेड गारमेंट उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को रु.5,000 प्रति माह इंसेंटिवमिलेगा।

प्रदेश में रोजगार के नए अवसर

- 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तीहोगी।
- पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ होंगी।
- हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास

- चित्रकूट धामको अयोध्या की तरह विकसित किया जाएगा।
- भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थलियों कोतीर्थ स्थलों के रूप में विकसितकिया जाएगा।
- सिंहस्थ-2028 के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "हर खेत तक पानी पहुंचे, हर हाथ को काम मिले और हर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो"—इसी लक्ष्य के साथ सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

ग्रीष्मकालीन मूंग फसल में कीटनाशक और नीदानाशक का उपयोग कम से कम करें : कृषि मंत्री श्री कंषाना

कीटनाशक और नीदानाशक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है

ग्रीष्मकालीन मूंग में अत्यधिक रासायनिक दवाओं का उपयोग हानिकारक

प्रदेश में 14.39 लाख हेक्टेयर में उगाई जा रही है ग्रीष्मकालीन मूंग फसल

भोपाल : किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने किसानों से अपील की है कि वे ग्रीष्मकालीन मूंग फसल में कीटनाशक एवं नीदानाशक का उपयोग कम से कम करें। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने बताया कि मूंग फसल में अत्यधिक रासायनिक दवाओं का दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य, जल एवं पर्यावरण पर सामने आया है। ऐसे में वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों की ओर से कई तरह की बीमारियां जन्म लेने की आशंका व्यक्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान भाई मूंग फसल की पैदावार के लिए ऐसा चक्र अपनाएं, जिससे ग्रीष्मकालीन मूंग प्राकृतिक रूप से अपने समय पर पक सके।

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर कहा कि यद्यपि मूंग की पैदावार से प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि हुई है। किसान इसे जल्दी पकाने के लिए कई बार नीदानाशक दवा (पेराक्वाट डायक्लोराइड) का छिड़काव करते हैं। इस दवा के अंश मूंग फसल में कई दिनों तक विद्यमान रहते हैं, जो मानव स्वास्थ्य एवं पशु-पक्षियों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।

कृषि मंत्री श्री कंषाना ने बताया कि कृषि एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों, पर्यावरणविद् और कृषि सुधार के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों ने अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर मूंग फसल में आवश्यकतानुसार ही कीटनाशकों के उपयोग का सुझाव दिया है। राज्य सरकार जैविक खेती को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है एवं किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

प्रदेश के नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, नरसिंहपुर, बैतूल, जबलपुर, विदिशा, देवास और रायसेन में सहित कई जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग किसानों के लिए तीसरी फसल का अच्छा विकल्प बन चुकी है। वर्तमान में मूंग की फसल 14.39 लाख हेक्टेयर रकबे में लगाई जा रही है और इसका उत्पादन 20.29 लाख मीट्रिक टन है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का औसत उत्पादन 1410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

पीएमबीजेकेएस का संचालन करने वाली पैक्स

नई दिल्ली: देश भर में 2,744 पैक्स (पीएसीएस) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थापित करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई), फार्मास्यूटिकल्स विभाग और भारत सरकार से प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। प्रारंभिक मंजूरी पाने वाले 2,744 पैक्स में से 785 को राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा दवा लाइसेंस जारी किए गए हैं और 716 पैक्स को पीएमबीआई द्वारा स्टोर कोड आवंटित किए गए हैं, जो पीएमबीजेके के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

पीएमबीजेके के रूप में काम करने वाले पीएसीएस लगभग 2,047 गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ और लगभग 300 सर्जिकल आइटम उपलब्ध कराते हैं। उत्पाद टोकरी में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह जैसे कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक्स, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक, गैस्ट्रो-आंत्र संबंधी दवाइयां, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि शामिल हैं। ये केंद्र ग्रामीण नागरिकों को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं जो ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती हो जाती है। इस पहल का उद्देश्य आवश्यक दवाओं तक पहुँच में सुधार करना, स्वास्थ्य सेवा की लागत को कम करना और ग्रामीण समुदायों की समग्र भलाई में सुधार करना है।

पीएमबीजेके का संचालन करने वाली पैक्स अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने में सक्षम रही हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ी है। पीएमबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक पीएमबीजेके का संचालन करने वाली पैक्स ने पीएमबीआई से 4.9 करोड़ रुपये की दवाइयाँ खरीदी हैं। इस पहल ने पैक्स की वित्तीय व्यवहार्यता को मजबूत किया है, जिससे उन्हें अन्य सहकारी गतिविधियों में फिर से निवेश करने, अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने और ग्रामीण आर्थिक विकास में अपनी भूमिका का विस्तार करने में मदद मिली है।

महिला सशक्तिकरण हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण संपन्न

महिलाओं कोसहकारी समितियों के गठन, पंजीयन और संचालनकी विस्तृत जानकारी दी गई।

सहकारी समितियों कीआर्थिक मजबूती, वित्तीय प्रबंधन, सरकारी योजनाओंऔर उनके लाभों पर गहन चर्चा की गई।

महिला सहकारी समितियों के माध्यम से स्वावलंबनकी दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जबलपुर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सहकारी समितियों से जोड़ने के उद्देश्य से सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर में कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यहदो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 मार्च से 21 मार्च 2025तक सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा किया गया, जिसमें सोमी महिला बहुद्देशीय सहकारी समितियों की संचालिकाओं एवं सदस्यगण ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली, नेतृत्व क्षमता एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षित करना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग, जबलपुर, श्री शंकर कुमार पांडेने महिलाओं को संगठित होकर आर्थिक रूप से सशक्त बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने सहकारी समितियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए महिलाओं को सहकारी आंदोलन से जुड़ने का आग्रह किया।

विशिष्ट अतिथि महिला एवं शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. विदुषी महिलाने महिलाओं के लिए सहकारिता की उपयोगिता को रेखांकित किया और उनके आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।

विशेष अतिथि सांची के महाप्रबंधक श्री कमल यादव ने अपने भाषण में इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों के अधिकाधिक आयोजन पर बल दिया, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं सहकारी आंदोलन का लाभ उठा सकें।

सहकारी संघ के प्रबंधक श्री रोहित बाजपेयी ने सहकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की और महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इस दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में सहकारिता क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों ने महिलाओं को सहकारी समितियों के संचालन, पंजीकरण, वित्तीय प्रबंधन एवं सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी : -

केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही. के. बर्वे – उन्होंने सहकारी समितियों के महत्व और उनके सफल संचालन की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपने हित में सहकारी समितियों का गठन कर आर्थिक रूप से सशक्त बनना चाहिए। **पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक** – उन्होंने सहकारी समितियों की कानूनी प्रक्रिया, उनके पंजीकरण एवं संचालन की विधि पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया। **मास्टर ट्रेनर श्रीमती मोनिका मुदगल** – उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व कौशल विकसित करने के तरीके सिखाए और बताया कि कैसे वे सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी सामूहिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं।

मास्टर ट्रेनर श्रीमती किरण भारद्वाज – उन्होंने वित्तीय प्रबंधन और सहकारी समितियों में पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर महिलाओं को उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। **जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री राकेश वाजपेयी** – उन्होंने सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली, उनकी संभावनाओं और महिलाओं के लिए विशेष सहकारी योजनाओं की जानकारी दी। **केन्द्र के प्रशिक्षक श्री पीयूष रॉय** – उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवसायिक अवसरों और स्वरोजगार की संभावनाओं पर व्याख्यान दिया।

केन्द्र के प्रशिक्षक श्री जय कुमार दुबे – उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मार्गदर्शन किया। **केन्द्र के प्रशिक्षक श्री अखिलेश उपाध्याय** – उन्होंने सहकारी समितियों के प्रबंधन, लेखांकन और संगठनात्मक संरचना की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम कासंचालन प्रशिक्षक श्री जय कुमार दुबे ने किया और अंत में आभार प्रदर्शन श्री एन. पी. दुबे द्वारा किया गया।

पंथपिपलई में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण सम्पन्न

दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं संचालक सदस्यों को नवाचार, सहकारिता एवं कार्यप्रणाली में सुधार के महत्वपूर्ण सुझाव

उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर एवं भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, नई दिल्लीके संयुक्त तत्वावधान मेंउज्जैन जिले की दुग्ध सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं संचालक सदस्योंके लिए पंथपिपलई में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी समितियों को सशक्त बनाना, दुग्ध उत्पादन में नवाचार लाना एवं समितियों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त, जिला उज्जैन श्री के. पाटनकर एवं विशेष अतिथि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दुग्ध सहकारी संघ उज्जैन, श्री डी. के. पाण्डे के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई।

उपायुक्त श्री के. पाटनकर ने अपने संबोधन मेंदुग्ध समितियों को नवाचार की दिशा में कार्य करने एवं दुग्ध उत्पादों के विविधीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ अन्य दुग्ध उत्पादों को भी विकसित करने से सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

विशेष अतिथि श्री डी. के. पाण्डेने प्रशिक्षार्थियों को दूध की गुणवत्ता सुधारने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने NDDB से विलय के बाद दुग्ध समितियों की कार्यप्रणाली में आने वाले संभावित सुधारों पर भी चर्चा की, जिससे समितियों को अधिक लाभ होगा।

- श्री एस. के. सोनी (दुग्ध संघ) –"सहकार से समृद्धि" विषय पर प्रशिक्षार्थियों से चर्चा की एवं सहकारी आंदोलन की सफलता पर प्रकाश डाला।
- श्री संजीव शर्मा (उपायुक्त कार्यालय) –अमूल के उदाहरण से बताया कि किस तरह दुग्ध सहकारी समितियाँ सहकारिता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रही हैं।
- श्री दिलीप मरमट (प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर)–संचालक सदस्य के अधिकार, कर्तव्य, आम सभा एवं बैठकों की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी।
- श्री सुयश शर्मा (प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर) –सहकारिता की पृष्ठभूमि, इतिहास एवं सिद्धांतों पर प्रकाश डाला।
- श्री प्रदीप कुमार रैकवार–नवाचार के प्रमुख बिंदुओं को साझा किया, जिससे समितियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके।
- श्री राहुल श्रीवास – सायबर सुरक्षा के महत्व पर जानकारी दी एवं डिजिटल प्रणाली में सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षार्थियों को आदर्श दुग्ध सहकारी समिति आलमपुर उड़ाना का अध्ययन भ्रमण भी करवाया गया, जिससे वेसफल सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझ सकें एवं उसे अपने कार्य में लागू कर सकें। कार्यक्रम के अंतिम दिवस परसभी प्रशिक्षार्थियों को बैग वितरित किए गए, जिससे उन्हें इस आयोजन की स्मृति बनी रहेइस अवसर परउज्जैन जिला सहकारी संघ से श्री सुमेर सिंह सोलंकी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।